दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 14 सितम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-01, अंक- 345

महत्वपूर्ण एवं खास

केंद्र सरकार ने 312 विदेशी सिखों को ब्लैक-लिस्ट से हटाया

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने विदेशी सिखों के मामले में एक बड़ी घोषणा करते हुए 312 सिखों को ब्लैक लिस्ट से हटा दिया है। इन सभी को देश विरोधी गतिविधियों के कारण ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे 312 विदेशी सिखों के नाम काली सूची से हटा दिए गए हैं। अब इस सूची में सिर्फ दो नाम बचे हैं। यह फैसला विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की ओर से काली सूची में दर्ज विदेशी सिख नागरिकों के नामों की समीक्षा के बाद लिया गया। एक अधिकारी ने बताया, 'भारत सरकार ने काली सूची में सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 314 विदेशी नागरिकों के नामों की समीक्षा की और अब इस सूची में सिर्फ दो नाम हैं।' इस काली सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, वह अब भारत में अपने परिवारों से मिलने आ सकते हैं और अपनी जमीन से दोबारा जुड़ सकते हैं। 1980 में देश में रहने वाले सिख समुदाय के कुछ लोग और विदेशों में रहने वाले कुछ सिख देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए इसी दौरान कुछ सिखों ने देश से जाकर विदेशों में शरण ले ली थी। इसके बाद उन्होंने वहां की नागरिकता भी ले ली थी। ये सभी 2016 तक ब्लैक लिस्ट में शामिल रहे। इन सभी को भारत यात्रा की अनुमति नहीं थी।

आईएनएक्स मीडिया केस में सरेंडर करने की याचिका खारिज

» चिदंबरम को झटका

नई दिल्ली (आरएनएस)। आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाली याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने यहां खारिज कर दिया। चिदंबरम पर आरोप है कि वर्ष 2007 में उन्होंने वित्तमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये के विदेशी धन को प्राप्त करवाने के लिए मंजूरी दिलवाई थी। वह इसी मामले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। ईडी ने बुधवार को उनके व्यक्तिगत स्टॉफ से भी मामले को लेकर पूछताछ की थी। वर्तमान में आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच के चलते चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी को संदेह है कि चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की कई संपत्तियां हैं और इसके अलावा दूसरे देशों में 16 बैंक खाते भी हैं। एजेंसी धन का पता लगाने में जुटी है।

बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे जज का कार्यकाल बढ़ा

नई दिल्ली (आरएनएस)। अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश एस के यादव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा न्यायालय के आदेश पर अमल करने के बारे में पेश हलफनामे और ऑफिस मेमो का अवलोकन किया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ को सूचित किया कि शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन किया जा चुका है और विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल अयोध्या विध्वंस मामले में फैसला सुनाये जाने की अवधि तक बढ़ा दिया गया है। पीठ ने मामले का निबटारा करते हुए कहा, ''हम संतुष्ट है कि आवश्यक कदम उठाये गये हैं। शीर्ष अदालत ने 23 अगस्त को राज्य सरकार से कहा था कि अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश द्वारा न्यायालय को भेजे गये पत्र में किये गये अनुरोध पर गौर किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करके कार्यकाल बढ़ाया है।

इमरान खान का कबूलनामा : पाक ने ही दी जेहादियों को ट्रेनिंग, अमेरिका ने दिया पैसा

इस्लामाबाद । प्रधानमंत्री इमरान खान एक के बाद एक पाकिस्तान की नापाक करतूतों को कबूल कर रहे हैं। इमरान खान ने अब कबूल किया है कि 1980 में अफगानिस्तान में रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान ने जेहादियों को तैयार किया था। उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। इमरान खान ने कहा है कि उनके देश को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ देने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। पाक पीएम ने कहा कि अमेरिका ने अंत में अफगानिस्तान में अपनी नाकामी

का दोष पाकिस्तान के सिर पर मढ़ दिया जोकि सही नहीं है। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कबूल किया कि शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने ही जिहादियों को तैयार किया था जिसकी फंडिंग अमेरिका ने ही की थी। लेकिन एक दशक बाद अमेरिका ने इन्हीं जिहादियों को आतंकवादी घोषित कर दिया। 70 हजार लोगों की गंवाई जिंदगी

इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि यह सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि हमने इस समूह का साथ देकर क्या पाया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इससे अलग रहना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका का साथ देकर हमने इन समूहों को पाकिस्तान के खिलाफ कर लिया। हमने इस दौरान बड़ी संख्या में कुर्बानी दी। लगभग हमने 70 हजार लोगों की जिंदगी गंवाई। साथ ही इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ है।

अमेरिकी एजेंसी सीआइए ने दिया जेहादियों को तैयार करने का पैसा

इमरान खान ने बताया कि 1980 के दशक में पाकिस्तान मुजाहिद्दीन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था, ताकि जब सोवियत यूनियन, अफगानिस्तान पर कब्जा करेगा तो वो उनके खिलाफ जेहाद का एलान करे देंगे। इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान को पैसा अमेरिका की एजेंसी सीआइए द्वारा दिया गया था। हालांकि, अमेरिका का नजरिया एक दशक बाद बिल्कुल बदल गया। अमेरिका, अफगानिस्तान में आया तो उसने उन्हीं समूहों को जो पाकिस्तान में थे, जेहादी से आतंकवादी होने का नाम दे दिया। अब इसे क्या कहा जा सकता है।

आतंकी संगठन पर खर्च किए करोड़ों रुपये

हाल ही में पाकिस्तान के मंत्री ने भी उसके चेहरा से पर्दा उठाते हुए बताया कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठन जमात-उद-दावा पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। राष्ट्रीय टेलीविजन पर देश के आंतरिक मंत्री ब्रिगेडियर (आर) एजाज अहमद शाह ने खुलासा किया है। शाह ने कहा कि इमरान सरकार ने आतंकी संगठन को मुख्यधारा से जुड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन के सदस्यों को मुख्यधारा में लाने की जरूरत है। इससे पहले, जुलाई में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कबूल किया था कि उनके देश में अभी भी 30,000 से 40,000 आतंकवादी मौजूद हैं। जिन्हें अफगानिस्तान और कश्मीर के हिस्सों में ट्रेनिंग दी गई।

चंद्रयान 2 विक्रम में इसरो का सहयोग करेगा नासा

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत के लिए अच्छी खबर है। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का सहयोग कर रहा है। नासा चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम की लैंडिग से पहले और बाद की तस्वीरों को इसरो के साथ शेयर करेगा। इससे विक्रम को लेकर किए जा रहे अध्ययन में सहायता मिलेगी।

इसरो के एक अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (जेपीएल) विक्रम को रेडियो सिग्नल भेज रही है। नासा अपने मून ऑर्बिटर की मदद से विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा है। इसरो भी लैंडर के साथ संपर्क साधने के लिए बंगलूरू के पास स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क (आईडीएसएन) के एंटेना का इस्तेमाल कर रहा है।

नासा ने चांद की सतह पर गतिहीन पड़े विक्रम लैंडर से संपर्क साधने के लिए उसे हैलो मैसेज भेजा है। अपने डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क के माध्यम से नासा के जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी (जेपीएल) ने लैंडर के साथ संपर्क साधने के लिए विक्रम को एक रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजी है। नासा के एक सूत्र ने इस बात की पुष्टि की है।

गणेश विसर्जन के दौरान पलटी नाव , 11 लोगों की हुई मौत

» छःलोगों को बचाया गया

» मुख्यमंत्री ने दिए न्यायिक जांच के आदेश

» मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा

भोपाल (आरएनएस)। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार की सुबह गणेश की प्रतिमा विसर्जन के दौरान स्थानीय छोटी झील में

नाव पलटने से उसमें सवार करीब डेढ़ दर्जन लोगों के डूबने के बाद छः लोगों को स्थानीय लोगों के माध्यम से बचा लिया गया है जबकि इस नाव दुर्घटना 11 लोगों की डुबने से मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह करीब साढ़े चार बजे हुए इस हादसे की सूचना मिलते ही वहां पहुंचे राहत दल ने छह लोगों को झील में से सुरक्षित निकाल लिया। मौके पर मौजूद विधि मंत्री पी सी शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि नाव में एक पूरी उत्सव समिति के सदस्य सवार थे। वे जैसे ही बड़ी मूर्ति का विसर्जन करने लगे, नाव अचानक पलट गई। मरने वाले सभी 11 लोग नवयुवक थे। छह लोग बचा लिए गए हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हादसे को बेहद दुखद बताते हुए इसकी मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुःख की इस घड़ी में सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उनकी हरसंभव मदद की जायेगी। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को सरकार की तरफ़ से 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश जारी किये हैं।

उन्होंने कहा कि इस घटना में जाँच में जिसकी भी लापरवाही सामने आयेगी, उसे छोड़ा नहीं जायेगा। प्रशासन की ओर से विर्सजन के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एनडीआरएफ की टीम के साथ ही पुलिस के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है।

डूसू में लहराया एबीवीपी का परचम

» तीन पदों पर जमाया कब्जा, एनएसयूआई को महज एक सीट

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव में भाजपा से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने शुक्रवार को अध्यक्ष सहित तीन पदों पर कब्जा जमाया। कांग्रेस समर्थित भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ एनएसयूआई को महज सचिव पद पर संतोष करना पड़ा। एबीवीपी के अश्वित दहिया ने अध्यक्ष पद के लिए नेशनल एनएसयूआई के चेतन त्यागी को 19 हजार वोटों से हरा दिया। एबीवीपी के प्रदीप तंवर और शिवांगी खरवाल उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पद पर जीते। इनके जीत का अंतर क्रमशः 8574 और 2914 वोटों का था। एनएसयूआई ने सचिव पद पर जीत हासिल की और इसके उम्मीदवार आशीष लांबा ने एबीवीपी के योगी राठी को 2053 वोटों से हराया।

गौरतलब है कि डूसू चुनावों में गुरुवार को करीब 40 फीसदी वोट पड़े जो पिछले साल के मुकाबले करीब चार फीसदी कम थे। बीते साल के चुनाव में 44.46 फीसदी वोट पड़े थे। मतदान ईवीएम से कराए गए थे। चुनाव में 16 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। इनमें चार महिलाएं थी। गुरूवार को 52 मतदान केंद्रों पर छात्रों ने वोट डाले थे।

करीब 1.3 लाख छात्र चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य थे. 144 ईवीएम छात्र संघ चुनाव के लिए और 137 ईवीएम कॉलेज संघ चुनाव के लिए इस्तेमाल की गई. मॉर्निंग क्लासेज के लिए मतदान सुबह साढ़े नौ बजे शुरू हुआ और दोपहर एक बजे खत्म हुआ. इवनिंग क्लासेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए दोपहर तीन बजे मतदान शुरू हुआ और यह शाम साढ़े सात बजे खत्म हुआ. पिछले साल तीन पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और एक पर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने जीत दर्ज की थी.

चिन्मयानंद के आश्रम पर एसआईटी का घेरा

» आने जाने वालों पर पुलिस की निगाह

शाहजहांपुर (आरएनएस)। यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री व भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद के इर्द-गिर्द (विशेष जांच दल)एसआईटी की घेराबंदी बढ़ती जा रही है। गुरुवार देर रात 2 बजे तक चिन्मयानंद और उनके कुछ विश्वासपात्रों से एसआईटी ने करीब 6-7 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। पूछताछ शाहजहांपुर पुलिस लाइन परिसर में की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, भले ही एसआईटी की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय विशेष पीठ कर रही हो, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए सूबे की सरकार और राज्य पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह करीब से नजर रखे हुए हैं।

शाहजहांपुर में कई दिन से डेरा डाले एसआईटी टीम के सदस्य आरोपी-गवाह और शिकायतकर्ताओं के अलावा बाकी हर किसी से दूरी बनाए हुए हैं। वजह है कि एसआईटी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की विशेष पीठ की नजरें लगी हुई हैं। जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? जांच की दिशा क्या है? इसकी पल-पल की जानकारी पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह को एसआईटी दे रही है,ताकि एसआईटी जब रिपोर्ट के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यी पीठ के सामने पेश हो, तो राज्य सरकार और राज्य पुलिस की किरकिरी न हो।

शाह ने स्वीकारा, कश्मीर पर दुनिया हमारा यकीन नहीं करती

इस्लामाबाद। इमरान खान सरकार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी के तौर पर उनके आंतरिक मामलों के मंत्री ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) एजाज अहमद शाह ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन पाने में नाकाम रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कश्मीर को लेकर पाकिस्तान पर नहीं बल्कि भारत पर यकीन है।

शाह ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा, हम कहते हैं कि उन्होंने (भारत) कर्फ्यू लगा दिया है, वहां के लोगों के लिए दवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोग (दुनिया) हमारी बातों का यकीन नहीं करते हैं और भारत पर विश्वास करते हैं।

शाह ने कहा कि देश पर राज कर रहे अभिजात वर्ग ने देश को बर्बाद कर दिया। आंतरिक मामलों के मंत्री ने यह भी कहा कि इमरान खान सरकार सभी प्रतिबंधित संगठनों जैसे हाफिज सईद के जमात उद-दावा (जेयूडी)और मसूद अजहर के जैश-ए-मोहम्मद को मुख्यधारा में लाएगी। उन्होंने

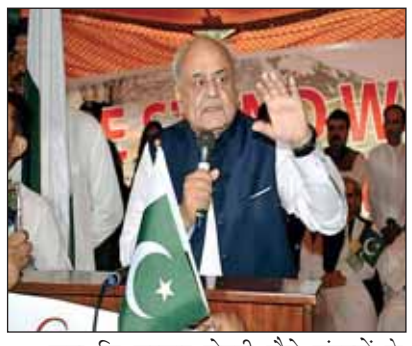

कहा कि सरकार जेयूडी जैसे संगठनों के खिलाफ कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा, वे अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, वे पाकिस्तानी हैं और उनसे लड़ने के लिए कहा गया था और वे प्रेरित हुए और अब उनका हौसला कम करने का काम कर रहे हैं और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिहादियों पर लगाम लगाने के सरकार के फैसले के रूप में हाफिज सईद को अदालतों में मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव: भाजपा मजबूत मगर सीट बदलना चाहते हैं जाट नेता

» जाटबहुल की जगह गैरजाट बहुल सीटों से लड़ना चाहते हैं चुनाव

» दलबदलुओं पर इस बार कम होगी नजरे इनायत

» एक तिहाई विधायकों का टिकट कटना तय

नई दिल्ली (आरएनएस)। विपक्ष में बिखराव के कारण हरियाणा में भाजपा की स्थिति बेहद मजबूत मानी जा रही है। पार्टी भी विधानसभा चुनाव में एक और जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। इसके बावजूद जाट बिरादरी के आधा दर्जन विधायक और मंत्री अपनी पुरानी सीट की जगह नई सीट से चुनाव लडना चाहते हैं। इनकी पसंद जाटबहुल नहीं बल्कि गैरजाट बहुल सीट हैं। बीते चुनाव में दलबदलुओं पर मेहरबान रही पार्टी इस बार अरसे से पार्टी से जुड़े नेताओं पर दांव लगाना चाहती है।

दरअसल लोकसभा चुनाव में पार्टी ने राज्य में विपक्ष का सूपड़ा तो साफ कर दिया था, मगर जाट और मुस्लिमबहुल सीटों पर विपक्ष से पार नहीं पा सकी थी। इस चुनाव में पार्टी को राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 79 सीटों पर बढ़त मिली थी। पार्टी को जाट और मुस्लिम बहुल 11 सीटों पर मोदी लहर के बावजूद सफलता नहीं मिल पाई थी। इनमें जाट बिरादरी के कद्दावर दो मंत्री भी शामिल थे। यही कारण है कि इस बिरादरी से जुड़े नेता इस बार गैरजाट बहुल सीट पर चुनावी किस्मत आजमाना चाहते हैं। इसके लिए इस बिरादरी के नेता अपने अपने तरीके से पार्टी नेतृत्व के समक्ष गुहार भी लगा रहे हैं।

दलबदलुओं पर नहीं बरसेगी मेहरबानी- चुनाव में इस बार पार्टी दलबदलुओं से ज्यादा अरसे से पार्टी से जुड़े रहे नेताओं पर ज्यादा भरोसा करेगी। सूत्रों का कहना है कि चूंकि इस बार राज्य में पार्टी की स्थिति बेहद मजबूत है। इसलिए तय किया गया है कि टिकट के मामले में पार्टी के खांटी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया जाए। इससे राज्य में विश्वस्त और निष्ठावान नेताओं की टीम खड़ी होगी। दूसरे दलों से आए कद्दावर नेताओं को ही पार्टी को टिकट मिलेगा। गौरतलब है कि पिछली बार पार्टी ने करीब दो दर्जन सीटों पर दलबदलुओं को उम्मीदवार बनाया था।

एक तिहाई विधायकों का टिकट कटना तय- पार्टी ने बीते छह महीने में सीट वार तीन बार विधायकों की स्थिति की समीक्षा की है। पार्टी के 47 में से 24 विधायकों-मंत्रियों के प्रति उनकी सीटों पर गहरी नाराजगी है। ऐसे में नेतृत्व कम से कम एक तिहाई विधायकों का टिकट काटेगी।